

श्रमबल में लैंगिक असमानता

सारांश

एनएसएसओ के 68वें राउंड 2011-12 में महिला श्रमिकों की सहभागिता दर 25.5 प्रतिशत थी। हाल के वर्षों में महिला सहभागिता दर में कमी आयी है इस कमी के कारणों में आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव एवं यू (U) आकार की परिकल्पनाओं के साथ-साथ पारिवारिक सामाजिक रूढ़िवादी सोच और महिलाओं के साथ हिंसा और यौन हिंसा कार्यस्थल पर पुरुषों के साथ रोजगार के अवसर की असमानता के कारण न सिर्फ करोड़ों महिलाओं का जीवन स्तर निम्न है जिससे न सिर्फ नैसर्गिक विकास में बाधा आ रही है बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक स्वास्थ्य को भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है इसलिए भारत के नीति निर्माताओं को गंभीर आर्थिक अवसरों, कानूनी संरक्षण और भौतिक सुरक्षा को एक आन्दोलन के रूप में अपनाना होगा जिससे रोजगार में लैंगिक समानता प्राप्त की जा सके।

मुख्य शब्द : श्रमबल, लैंगिक असमानता, भारतीय अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

उदारीकरण के बाद जब भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से संवृद्धि की ओर बढ़ी तो यह संवृद्धि श्रम गहन न हो करके पूंजी गहन रही जिस कारण रोजगार के अवसरों में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी गई और इस संवृद्धि को रोजगार विहीन संवृद्धि कहा गया। जिस कारण कुल रोजगार के अवसरों की कमी हुई ऐसी अवस्था में जब पुरुषों के लिए ही रोजगार के अवसरों की कमी हो तो महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाने की बात भारत जैसे पितृ सत्तात्मक समाज में जटिल प्रतीत होती है। इस रोजगार विहीन संवृद्धि में ट्रिकल डाउन नीति पर जोर श्रम सुधारों में सुस्ती, समष्टिभावी रोजगार नीति का न होना एवं निजी और सार्वजनिक निवेश में कमी प्रमुख कारण रहें हैं। लेकिन भारत में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है परंतु उनका जीडीपी में योगदान 17.1 प्रतिशत है जो वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर 50 प्रतिशत महिलायें श्रमशक्ति का हिस्सा बन जायें तो भारत की विकास दर 1.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

साहित्यावलोकन

अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों द्वारा सामान्य स्थिति एवं गौड़ स्थिति (पीएस + एस.एस.) को साथ ले कर अध्ययन सामने आये हैं। जिससे यह बात सामने आ रही है कि श्रमबल में कमी का कारण मुख्यतः महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी में आ रही कमी प्रमुख है। सी. रंगराजन ने इस बात की ओर संकेत किया है कि 1977 से 2004-05 के बीच ग्रामीण महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी 33 प्रतिशत के आस-पास थी। जो 2004-05 से 2011-12 के बीच 25 प्रतिशत के करीब रही। श्रमबल में इस कमी का कारण सी. रंगराजन (2014) ने अपने इसी आलेख में बताया है – शिक्षा का प्रभाव – श्रम शक्ति में शामिल होने के स्थान पर ग्रामीण महिलाओं का बढ़ती संख्या में शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास। 1999-2000 में 18 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं शिक्षा में शामिल थीं। 2011-12 में इनका प्रतिशत बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया। (15-24) आयु वर्ग की महिलाओं में शिक्षा में शामिल होने का प्रतिशत 1999-2000 में 43 प्रतिशत था वो 2011-12 में बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया। कन्नन एवं रविन्द्रन (2012) ने अपने आलेख में यह बताया है कि (30-34) आयु वर्ग की महिलाओं में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गयी है। नेफ (2012) ने भी महिलाओं के सभी आयु वर्ग में कमी का उल्लेख करते हैं एवं आयु वर्ग के आधार पर पुरुषों में भी गिरावट है जो केवल (15-19) एवं (20-24) आयु वर्ग तक ही सीमित है।

सी. रंगराजन (2011) विश्लेषित करते हैं कि 61वें दौर में जहां 625 मिलियन लोग श्रमबल से बाहर वहीं 66वें दौर में इनकी संख्या बढ़कर 707 मिलियन हो गयी। श्रमबल में आई कमी का कारण श्रम बाजार में कामगारों के



प्रशान्त

शोध छात्र,
अर्थ शास्त्र विभाग,
गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक
विज्ञान संस्थान,
झूसी, प्रयागराज, उ०प्र०
भारत

कई वर्गों में आ रही कमी के कारण है इसे वे चार श्रेणियों में विभाजित करते हैं—

1. 44 प्रतिशत लोग अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ भविष्य में बेहतर रोजगार की संभावनाओं के कारण शिक्षा में नामांकनों में बढ़ोत्तरी में शामिल है।
2. 31 प्रतिशत महिलाओं का श्रमबल में जाने के बजाय घरेलू कार्य को प्राथमिकता देना मानते हैं।
3. 0-4 आयु वर्ग के बच्चों का श्रमबल से बाहर जाना।
4. अक्षम लोगों पेंशन प्राप्त कर्ताओं एवं रिटायर्ड लोगों का 10 प्रतिशत जो श्रम बल से बाहर हो गये। अपने इसी आलेख में रंगराजन आगे कहते हैं कि सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार विधेयक, युवाओं एवं किशोरों का शिक्षा में अधिक भागीदारी लोगों को श्रमबल से दूर कर रही है।

आय प्रभाव को भी कुछ विशेषज्ञ श्रमबल में भागीदारी के कारणों में शामिल करते हैं। सी. रंगराजन 2014 अपने एक अन्य शोध पत्र में स्पष्ट करते हैं कि गाँवों में बढ़ते आय स्तर के कारण जो 1999-2000 के बीच 0.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष घरेलू व्यय दर से बढ़ रहा था या 2004-05 एवं 2011-12 के बीच 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोत्तरी हुई। इसी के साथ गाँवों में मजदूरी में बढ़ोत्तरी हुई जिसमें मनरेगा का योगदान उल्लेखनीय रहा है। इस कारण ग्रामीण महिलाएं जो श्रमबल में शामिल होती थीं उन्हें घर से बाहर जा कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं रही और वे श्रमशक्ति से बाहर हो गयीं और अपने घरेलू कार्यों में अधिक दिलचस्पी ले रहीं हैं। इसी तरह का विश्लेषण निशा श्रीवास्तव (2010) अपने आलेख में भी करती हैं।

निशा श्रीवास्तव (2010) ने अपने आलेख में महिलाओं की अन्य कई स्थितियों को विश्लेषण किया है जिसके कारण महिलाओं की रोजगार की स्थिति और अधिक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण हो जाती है। वे अपने लेख में कहती हैं कि 1972-73 से 2004-05 के बीच शहरी महिलाओं की स्थिति ग्रामीण महिलाओं की तुलना में बेहतर हुई है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति रोजगार के मामलों में काफी निम्न स्तर पर है। महिलाओं का पुरुषों की तुलना में कम वेतन, कार्य करने की खराब दशाएं, कार्यों में भेद-भाव, सामाजिक सुरक्षा की बेकार दशा, किसी रोजगारपरक कार्य करने के लिए कम पूँजी की उपलब्धता उसका मूल्य वर्धन कम होना, रोजगार की गुणवत्ता की दृष्टि में काफी सोचनीय स्थिति का होना, महिलाओं में शिक्षा एवं कौशल की कमी, संसाधनों तक कम पहुँच इत्यादि कारण महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों का पालन-पोषण, बच्चों की संख्या, परिवार के आकार जैसे कारकों पर अब्राहम (2011), रुचिका चौधरी (2014) अंसारी 2015 इत्यादि विशेषज्ञों ने विस्तार से अपने लेख में बताया है। यह लेख सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोधों पर जोर डालते हैं जिनके कारण किन्हीं खास वर्ग के लोग रोजगार के अवसरों से बहिष्कृत हो जाते हैं। यह लेख श्रम बल की संरचना को समझने में हमारी मदद करते हैं।

भारत में उदारीकरण के बाद न सिर्फ रोजगार की संवृद्धि में काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा बल्कि एक अस्पष्ट स्थिति भी बनी रही जिसका उल्लेख इंदिरा हिरवे (2012) ने अपने लेख "मिसिंग लेबर फोर्स एंड एक्सप्लेनेशन" में कुछ प्रश्नों के माध्यम से उठाती हैं। वे इसे निम्न प्रकार से आगे बढ़ाती हैं।

1. 2004-05 से 2009-10 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 8.6 प्रतिशत रही जबकि 2009-10 के एन.एस.एस.ओ. के सर्वेक्षणों में रोजगार की संवृद्धि दर 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही।
2. 2004-05 से 2009-10 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर 1.44 प्रतिशत रही जबकि इसी अवधि में रोजगार की वृद्धि दर अत्यंत न्यून रही फिर भी 2004-05 और 2009-19 बेरोजगारों की संख्या 11.5 मिलियन से कम होकर 9.7 मिलियन रह गयी।
3. 1993-94 एवं 1999-2000 के बीच कार्यबल में 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर रही। 1999-2000 से 2004-05 के बीच 2.85 प्रतिवर्ष हो गयी, 2004-05 से 2009-10 के बीच 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गयी जो कि एन.एस.एस.ओ. के विभिन्न सर्वेक्षणों के दौरान आये उतार-चढ़ाव एक पहेलीनुमा प्रतीत होते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि महिला कार्यबल को लेकर एक जटिल स्थिति बनी हुई। इस स्थिति को और जटिलता तब मिलती है जब रोजगार के पैमाने पर स्त्री एवं पुरुष को एक पैमाने पर मापा जाता है। साहित्य सर्वेक्षण अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों द्वारा पीएस और एसएस दोनों को साथ लेकर अध्ययन किये गये हैं। अतः अपने अध्ययन में हम निम्नवत तथ्यों की पडताल करेंगे।

1. महिलाओं की पीएस के आधार पर कृषिगत कार्यों का भारतीय राज्यों में 1993-94 में एवं 2011-12 के बीच विश्लेषण।
2. पीएस और एसएस को अलग-अलग करके यह देखना कि अंतरराज्यीय आधार पर महिलाओं की कार्यबल में स्थिति का वर्णन करना।
3. महिला श्रमिकों द्वारा कार्यबल में शामिल होने में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों का विश्लेषण करना।

शोध प्रविधि

इस लेख में नेशनल सैंपल सर्वे के 50वें एवं 68वें राउंड के डाटा का प्रयोग किया गया है जिसको स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस (एसपीएसएस) पर विश्लेषित किया गया है इस विश्लेषण में प्रतिशत परिवर्तन, वार्षिक चक्रवृद्धि दर का प्रयोग किया गया है।

1990 के शुरुआत से सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट से गुजरी महिलाओं और हासिये पर रहने वाले समूहों के लिए आय पैदा करने वाले अवसरों पर काफी दबाव पड़ा। जिस कारण कुल रोजगार के अवसरों की कमी हुई ऐसी अवस्था में जब पुरुषों के लिए ही रोजगार के अवसरों की कमी हो तो महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाने की बात भारत जैसे पितृ सत्तात्मक समाज में जटिल प्रतीत होती है। इस रोजगार विहीन संवृद्धि में

ट्रिकल डाउन नीति पर जोर श्रम सुधारों में सुस्ती, समष्टिभावी रोजगार नीति का न होना एवं निजी और

सार्वजनिक निवेश में कमी प्रमुख कारण रहे हैं।

सारिणी 1 : सामान्य स्तर पीएस के आधार पर 50वें दौर 1993-94) एवं 68वें दौर (2011-12) में ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यबल में क्षेत्रवार परिवर्तन

ग्रामीण (महिला)-	50वां दौर		68वां दौर		बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी		CAGR
	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	
कृषि	561	84.8	496	74.5	-65	-11.6	-0.7
खनन एवं उत्खनन	3	0.5	3	0.4	-1	-20.7	-1.3
विनिर्माण	49	7.5	64	9.5	14	28.7	1.4
बिजली, पानी एवं गैस आपूर्ति	0	0.0	1	0.1	0	127.7	4.7
निर्माण	6	1.0	34	5.1	27	428.7	9.7
सेवाएं	41	6.3	69	10.4	28	68.0	2.9
कुल	661	100	666	100	5	0.7	0.0

स्रोत- संकलित यूनिट रिकार्ड डाटा

(सारणी 1) को विश्लेषित करें तो 85 प्रतिशत कामगार महिलाएं कृषि में कार्य करती थी जोकि 2011-12 में इनकी वृद्धि 74 प्रतिशत थी जो यह दर्शाता है 180 दिनों जो कि मुख्य कार्य या पीएस में दिनों की संख्या दर्शाता है अभी भी महिलाओं की भागेदारी 70

प्रतिशत के आस पास है उदारीकरण के बाद भारत में नए शहरों के बनने की प्रक्रिया के कारण तथा नौकरियों का कुछ विस्तार गावों में भी हुआ जिनमें सेवाओं और निर्माण एवं विनिर्माण में महिलाओं की भूमिका बढ़ी।

सारिणी 2 : सामान्य स्तर पीएस के आधार पर 50वें दौर 1993-94) एवं 68वें दौर (2011-12) में नगरीय महिलाओं के लिए कार्यबल में क्षेत्रवार परिवर्तन

नगरीय(महिला)-	50वां दौर		68वां दौर		बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी		CAGR
	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	
कृषि	22	19.6	16	8.7	-5.3	-24.3	-1.5
खनन एवं उत्खनन	1	0.7	1	0.3	-0.1	-17.5	-1.1
विनिर्माण	26	23.7	50	26.6	23.9	91.2	3.7
बिजली, पानी एवं गैस आपूर्ति	0	0.3	2	1.1	1.7	451.4	9.9
निर्माण	5	4.9	8	4.3	2.7	50.4	2.3
सेवाएं	56	50.7	111	58.9	55.1	98.3	3.9
कुल	111	100	189	100	78.0288	70.6	3.0

स्रोत- संकलित यूनिट रिकार्ड डाटा

(सारणी 2) में शहरों में कृषि का हिस्सा नहीं होता है लेकिन शहरीकरण के कारण बड़े महानगरों टाउन के आस पास का क्षेत्र जहां पर उद्योगों का विकास हुआ

वहा कृषि में वृद्धि को नकारात्मक कर दिया। शहरों में महिलाओं को रोजगार सेवाओं सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी के अवसर बढ़ने से यहाँ रोजगार के इन क्षेत्रों में धीमी परन्तु स्थायी वृद्धि हुई है।

सारिणी 3.1: भारतीय राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 50वें दौर (1993-94) एवं 68वें दौर (2011-12) में ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं के लिए सामान्य स्तर पीएस के आधार पर कृषिगत कार्यों में कार्यबल में परिवर्तन-

राज्य	50वां दौर (लाख में)	68वां दौर (लाख में)	बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी (लाख में)	परिवर्तन (प्रतिशत)	CAGR
सिक्किम	0.1	0.9	0.8	651.1	11.9
नागालैण्ड	0.2	0.6	0.4	217.8	6.6
पश्चिम बंगाल	9.8	15.1	5.3	53.9	2.4
मिजोरम	0.6	0.8	0.3	48.6	2.2
हिमाचल	8.2	11.5	3.3	40.5	1.9
असम	5.6	6.7	1.1	19.7	1.0
त्रिपुरा	0.5	0.5	0.1	18.2	0.9
हरियाणा	3.0	3.5	0.5	15.9	0.8
मेघालय	2.7	2.9	0.2	7.3	0.4
गुजरात	28.5	29.5	1.0	3.5	0.2
राजस्थान	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0
आंध्रप्रदेश	92.5	88.9	-3.6	-3.9	-0.2
मध्यप्रदेश	68.0	65.0	-3.0	-4.4	-0.2

कर्नाटक	41.8	39.3	-2.5	-6.0	-0.3
अरुणाचल प्रदेश	1.1	1.1	-0.1	-7.2	-0.4
महाराष्ट्र	85.1	74.6	-10.5	-12.3	-0.7
उत्तर प्रदेश	60.7	52.9	-7.8	-12.9	-0.8
केरल	8.1	6.6	-1.5	-18.8	-1.2
दादर एवं नागर हवेली	0.1	0.1	0.0	-19.7	-1.2
पाण्डिचेरी	0.3	0.2	-0.1	-23.2	-1.5
पंजाब	1.6	1.1	-0.5	-29.5	-1.9
अण्डमान एवं निकोबार	0.1	0.1	0.0	-37.4	-2.6
उड़ीसा	24.9	15.6	-9.3	-37.5	-2.6
तमिलनाडु	60.9	36.2	-24.6	-40.5	-2.8
मणिपुर	0.8	0.4	-0.4	-45.8	-3.3
बिहार	34.8	16.6	-18.2	-52.3	-4.0
जम्मू एवं कश्मीर	0.8	0.4	-0.4	-52.7	-4.1
गोवा	0.3	0.1	-0.3	-82.5	-9.2
दमन एवं दीव	0.0	0.0	0.0	-89.0	-11.6
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	-91.3	-12.7
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	-100.0	-100.0
दिल्ली	0.2	0.0	-0.2	-100.0	-100.0

स्रोत— संकलित यूनिट रिकार्ड डाटा

सारणी 3.2

धनात्मक 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी वाले राज्य	सिक्किम, नागालैण्ड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा।
धनात्मक 10 प्रतिशत व ऋणात्मक 10 प्रतिशत के मध्य वाले राज्य	मेघालय, गुजरात, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश।
ऋणात्मक 10 प्रतिशत से अधिक कमी वाले राज्य	महाराष्ट्र तमिलनाडु, पंजाब, केरल, पाण्डुचेरी, गोवा, दिल्ली, दमन एवं दीव, चण्डीगढ़ लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अण्डमान एवं निकोबार।

सारणी 3.1 और 3.2 का विश्लेषण करने पर यह प्रदर्शित होता है कि 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी वाले राज्य में असम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अपेक्षाकृत छोटे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है साथ ही साथ हरियाणा में जहां महिलाओं की भागेदारी बढ़ी है वहां हरित क्रान्ति के कारण पैदावार में वृद्धि एवं दिल्ली से सटे होने के कारण कृषिगत उत्पादों की आपूर्ति पर अधिक ध्यान है। 10 प्रतिशत धनात्मक और 10 प्रतिशत ऋणात्मक कमी और

वृद्धि वाले राज्यों में गुजरात, कर्नाटक में मिला जुला है। 10 प्रतिशत से ऋणात्मक वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार में कमी उल्लेखनीय है क्योंकि यहाँ की भूमि पर ज्यादा दबाव है और भूमि बढ़ते परिवारों की वजह से कम हो रही है और लोग काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं लेकिन पंजाब एक समृद्धि राज्य है और कृषि में अग्रणी राज्य होने के कारण यहाँ महिलाओं का कृषि से अलग होना चौकाने वाला है।

सारणी 4.1 : सामान्य स्तर एसएस जिनका सामान्य स्तर पीएस भी है के आधार पर भारतीय राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए 50वें दौर एवं 68वें दौर में कृषिगत कार्यों में कार्यबल में परिवर्तन—

राज्य	50वां दौर (लाख में)	68वां दौर (लाख में)	बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी (लाख में)	परिवर्तन (प्रतिशत)	CAGR
नागालैण्ड	0.0	0.1	0.0	605.8	11.5
सिक्किम	0.0	0.1	0.0	423.5	9.6
जम्मू एवं कश्मीर	0.1	0.2	0.2	309.0	8.1
मेघालय	0.1	0.4	0.3	227.0	6.8
अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	100.4	3.9
त्रिपुरा	0.0	0.1	0.0	60.0	2.6
मिजोरम	0.0	0.0	0.0	26.2	1.3
मणिपुर	0.1	0.1	0.0	19.0	1.0
पंजाब	0.3	0.4	0.0	10.4	0.5
पश्चिम बंगाल	3.6	2.5	-1.1	-31.1	-2.0

मध्यप्रदेश	24.4	16.1	-8.2	-33.7	-2.3
लक्ष्यद्वीप	0.0	0.0	0.0	-34.0	-2.3
राजस्थान	12.3	7.5	-4.8	-38.9	-2.7
उड़ीसा	11.7	7.0	-4.7	-40.4	-2.8
हिमांचल	1.9	1.0	-0.8	-44.8	-3.2
केरल	2.8	1.5	-1.3	-45.8	-3.3
गुजरात	10.3	4.8	-5.6	-53.8	-4.2
हरियाणा	0.4	0.2	-0.2	-55.9	-4.4
महाराष्ट्र	34.8	13.8	-21.0	-60.4	-5.0
असम	0.5	0.2	-0.3	-66.4	-5.9
आंध्रप्रदेश	42.1	13.6	-28.5	-67.6	-6.1
उत्तर प्रदेश	22.7	5.6	-17.1	-75.4	-7.5
बिहार	7.7	1.9	-5.8	-75.8	-7.6
कर्नाटक	15.8	3.4	-12.4	-78.5	-8.2
तमिलनाडु	19.1	3.8	-15.3	-80.2	-8.6
दादर एवं नागर हवेली	0.0	0.0	0.0	-85.9	-10.3
पाण्डुचेरी	0.1	0.0	-0.1	-94.1	-14.5
अण्डमान एवं निकोबार	0.1	0.0	-0.1	-94.4	-14.8
गोवा	0.1	0.0	-0.1	-99.5	-25.8
दमन एवं द्वीप	0.0	0.0	0.0	-100.0	-100.0
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	-100.0	-100.0
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0		

स्रोत— संकलित यूनिट रिकार्ड डाटा

सारिणी 4.2

धनात्मक 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी वाले राज्य	नागालैण्ड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, पंजाब।
धनात्मक 10 प्रतिशत व ऋणात्मक 10 प्रतिशत के मध्य वाले राज्य	
ऋणात्मक 10 प्रतिशत से अधिक कमी वाले राज्य	पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, पाण्डुचेरी, गोवा, हरियाणा। दिल्ली दमन एवं द्वीप चण्डीगढ़ हिमांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मध्यप्रदेश, लक्ष्यद्वीप, कर्नाटक, दादर एवं नागर हवेली, आंध्रप्रदेश, अण्डमान एवं निकोबार।

(सारणी 4.1 और 4.2) वे महिलायें जो सिर्फ एसएस यानि साल भर में कम से कम तीस दिनों या उससे अधिक कार्य करती है। इसमें बड़े राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में तो महिलायें पुरुषों के पलायन की वजह से कृषिगत कामों में भागेदारी बढ़ी है लेकिन विकसित राज्यों पंजाब, महाराष्ट्र में कृषि में महिलाओं की भागेदारी बढ़ना इस बात का सूचक है कि

पुरुष अधिक आय वाले श्रोतों की तरफ जाते हैं और महिलाएँ अधिक श्रम और कम वेतन वाले कामों की ओर स्थानान्तरित होती हैं अगर 10 प्रतिशत से अधिक ऋणात्मक वाले राज्यों की बात करें तो काफी बड़े राज्य तमिलनाडु, केरल, हरियाणा अधिक आय या सामाजिक और आर्थिक संकेतों में ऊपर वाले राज्य हैं जहां महिलाओं की भागेदारी कम है।

सारिणी 5.1 : सामान्य स्थिति पीएस एवं दौनों गौड स्थितियों एसएस के आधार पर भारतीय राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए 50वें दौर एवं 68वें दौर में कृषिगत कार्यों में कार्यबल में परिवर्तन—

राज्य	50वां दौर (लाख में)	68वां दौर (लाख में)	बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी (लाख में)	परिवर्तन (प्रतिशत)	CAGR
सिक्किम	0.2	0.9	0.8	439.3	9.8
नागालैण्ड	0.4	1.1	0.8	205.6	6.4
जम्मू एवं कश्मीर	3.6	8.4	4.8	132.0	4.8
मिजोरम	0.6	0.8	0.3	43.8	2.0
मेघालय	2.9	3.3	0.4	14.8	0.8
पंजाब	13.7	14.9	1.2	8.4	0.4
हिमांचल	13.8	14.1	0.3	2.2	0.1

असम	10.9	11.0	0.1	0.9	0.0
त्रिपुरा	0.7	0.7	0.0	-3.8	-0.2
उत्तर प्रदेश	125.7	118.3	-7.4	-5.9	-0.3
अरुणाचल प्रदेश	1.1	1.1	-0.1	-6.1	-0.3
राजस्थान	76.6	68.4	-8.3	-10.8	-0.6
पश्चिम बंगाल	31.2	26.8	-4.4	-14.2	-0.8
मध्यप्रदेश	117.4	96.3	-21.1	-17.9	-1.1
महाराष्ट्र	135.5	109.9	-25.6	-18.9	-1.2
गुजरात	56.7	43.7	-13.0	-22.9	-1.4
आंध्रप्रदेश	147.4	108.8	-38.6	-26.2	-1.7
उड़ीसा	49.9	35.9	-14.0	-28.1	-1.8
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	-28.2	-1.8
केरल	18.6	12.7	-5.9	-31.6	-2.1
हरियाणा	16.5	11.2	-5.2	-31.8	-2.1
बिहार	54.2	34.9	-19.2	-35.5	-2.4
कर्नाटक	72.4	44.6	-27.9	-38.5	-2.7
पाण्डुचेरी	0.5	0.3	-0.2	-41.8	-3.0
मणिपुर	1.2	0.6	-0.5	-45.8	-3.3
तमिलनाडु	92.3	44.0	-48.3	-52.4	-4.0
अण्डमान एवं निकोबार	0.4	0.1	-0.3	-72.5	-6.9
दादर एवं नागर हवेली	0.3	0.1	-0.2	-73.5	-7.1
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	-83.2	-9.4
गोवा	0.7	0.1	-0.6	-90.6	-12.3
दमन एवं द्वीव	0.1	0.0	-0.1	-94.3	-14.7
दिल्ली	0.3	0.0	-0.3	-100.0	-100.0

स्रोत— संकलित यूनिट रिकार्ड डाटा

सारिणी 5.2

धनात्मक 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी वाले राज्य	जम्मू एवं कश्मीर, नागालैण्ड।
धनात्मक 10 प्रतिशत व ऋणात्मक 10 प्रतिशत के मध्य वाले राज्य	पंजाब।
ऋणात्मक 10 प्रतिशत से अधिक कमी वाले राज्य	लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, असम, पाण्डुचेरी, गोवा, हरियाणा, दिल्ली दमन एवं द्वीप चण्डीगढ़ हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, दादर एवं नागर हवेली, आंध्रप्रदेश, अण्डमान एवं निकोबार।

(सारिणी 5.1 और 5.2) अगर पीएस तथा एसएस दोनों को मिलाकर देखे तो अखिल भारत पर महिलाओं की कृषिगत कामों में भागेदारी सभी राज्यों में है नागालैण्ड एक छोटा प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर में भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रख कर विश्लेषण करें तो सभी बड़े भारतीय राज्यों में महिलाओं की कृषिगत कामों में कमी आयी है जिस कारण महिलाओं की भागेदारी में कमी हो रही है।

1993-94 एवं 2011-12 के बीच भारत की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन इस जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी महिलाओं की कार्यबल में बढ़ोत्तरी कम हुई होने के अनेकों कारण है जिसमें से महिलाओं की शिक्षा में भागेदारी में बढ़ोत्तरी जिस कारण महिलाएं कृषिगत कामों से अलग हो रही है। परिवार की औसत आय का बढ़ाना जिस कारण उनको घर के बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं रही। इन कारणों के

अलावा अगर सामाजिक रूढ़ियों, परिवार की जिम्मेदारी बच्चों बुजुर्गों की देखरेख इत्यादि है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुविधानुसार वातावरण का आभाव, रोजगार के अवसरों में असमानता भेदभाव, शोषण यौन हिंसा अपमान परम्परागत रूप से महिलाओं को कमजोर दिखाना ये सब कारण ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं जिससे महिलाएं औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार से कई बार जुड़ती हैं और अलग होती हैं मजदूरी में भेद-भाव इत्यादि कारणों से श्रमबल से बाहर हो जाती हैं और फिर कार्यबल में शामिल नहीं होती हैं महिलाओं के श्रमबल में भागेदारी बढ़ाने के लिए कई स्तर पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है कई महिला अपनी योग्यता की मान्यता के कारण समाज में दिन प्रतिदिन के सराहना की पात्र होती हैं लेकिन ज्यादातर महिलाएं इसका श्रेय नहीं पाती हैं जिस कारण वे अपनी क्षमता के कारण न्याय नहीं कर पाती हैं और अपने को सशक्त महसूस नहीं करती हैं यह

एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसे मानसिकता में बदलाव से दूर किया जा सकता है महिलाओं को पितृसत्ता जैसी शोषणकारी प्रणाली को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए।

ग्रामीण भारत के सामाजिक ढांचे में कृषि में कार्यरत महिला श्रमिकों की स्थिति दलित पुरुषों की तुलना से भी अधिक गंभीर है क्योंकि इन महिलाओं को लिंग के कारण होने वाले शारीरिक व मानसिक शोषण को समझना इतना आसान नहीं है और यह स्थिति अभी भी गतिमान है। इन महिलाओं का आर्थिक शोषण भी खूब होता है और कुछ अध्ययनों से यह बात भी सामने आयी है कि 1987-88 से 1993-94 एवं 1993-94 से 1999-2000 के बीच अधिकतर राज्यों में पुरुष तथा स्त्री श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में स्पष्ट गिरावट हुई। 1990 के दशक में विभिन्न जिलों एवं राज्यों के बीच वास्तविक मजदूरी दरों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी है। यह अंतर यही तक सीमित नहीं रहे बल्कि ये अंतर पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए बढ़ते गये। अधिकतर राज्यों में स्त्री और पुरुषों की मजदूरी न्यूनतम दर से भी कम रही अगर इस अंतर को स्त्री श्रमिकों के संदर्भ में देखें तो यह न्यूनतम में भी न्यून रही। इस प्रकार अधिकतर राज्यों में स्त्री श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में विषमता बढ़ रही है।

वर्तमान समय में कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है इसलिए खेती से जुड़े वे परिवार जिनके पास अधिक भूमि नहीं है। खेतिहर या बटाई मजदूरी पर कार्य करते हैं ऐसे परिवार की महिलायें अपने परिवार के साथ अंतर्राज्यीय या अंतःराज्यीय प्रदेशों में कार्य के लिए पलायन करते हैं क्योंकि वे परिवार खेतिहर मजदूरी की आय से अपनी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार की आशा नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण ईंट भट्टे या निर्माण क्षेत्र, हाईवे, बिल्डिंग, सडकें जैसे कम कौशल वाले रोजगार के क्षेत्रों में काम ढूंढते हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इन परिवार की महिलाओं का स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए लघु एवं कुटीर और कृषिगत उत्पादों से आसानी से मिल सकने वाले रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिसमें केंद्र या राज्य सरकारें अपनी नीतियों तथा बैंक वित्त एवं परिशिक्षण के माध्यम से खेतिहर, भूमिहीन महिलाओं की पारिवारिक आय तथा रोजगार में भागीदारी बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

श्रम का व्यवसायीकरण और पूंजी आधारित आर्थिक विकास के साथ-साथ तकनीकी का लैंगिक

विभाजन से कार्यबल महिलाओं की घटती भागेदारी इस बात को रेखांकित करती है कि महिलाओं के श्रमबल में प्रवेश करने से लेकर श्रमबल में बने रहने तक चुनौतियों के कई स्तर हैं। ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सभी क्षेत्रों में विद्यमान है इन चुनौतियों को भारतीय समाज की संस्कृतिक भाषायी नस्लीय भौगोलिक विविधता और बढ़ती है। इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भूमि अधिकार के मुद्दे को सुधारना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जागरूकता, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल पर सुविधाओं और कानूनों का कठोरता से लागू करने से ही महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी की व्यावहारिक चुनौतियों के स्थायी हल की ओर जाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अब्राहम वी (2013) मिसिंगलेबर ऑफ कंसिस्टेंट डी फीमिनाइजेशन इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली (99-108)।*
- डेनिएल नेफ (2014) द पजलिग इन रुरल वीमेन लेबर फोसे पार्टिसिपेशन इन इंडिया द जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (407-429)।*
- डोन्ट सूट द मैसेंजर (2011)।*
- इन्दिरा हिरवे (2012) मिसिंग लेबर फोर्स इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली (67-71)।*
- इंद्रानी मजुमदार (2011) जेंडर डायमेंशन ट्रेड इन इंडिया (1993-94) टू (2009-10) इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली।*
- निशा एंड रवि श्रीवास्तव (2010) वीमेन वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट आउटकम इन रुरल इंडिया इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली (49-63)।*
- एनएसएसओ। (1997) भारत में रोजगार और बेरोजगारी 50 वां दौर। नई दिल्ली: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।*
- एनएसएसओ। (1997) भारत में सामाजिक समूहों के बीच रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति। नई दिल्ली: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।*
- एनएसएसओ। (2012) 68 वें दौर में भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति। नई दिल्ली: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।*
- एनएसएसओ। (2012) भारत में सामाजिक समूहों के बीच रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति। नई दिल्ली: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।*